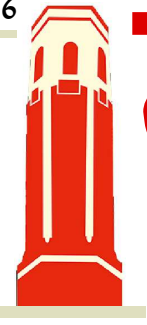


- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 262
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

चुनाव आयोग कार्यालय में बवाल ◆ संजय छेत्री समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में!

हमारे संवाददाता
देहरादून। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज आम आदमी पार्टी महानगर और युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता छह नंबर पुलिया स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर तालाबंदी करने पहुंचे।

जबरदस्त नारेबाजी के बीच जैसे ही कार्यकर्ताओं ने गेट में प्रवेश किया, मौके पर पहले से मौजूद भारी पुलिस बल ने अलोकतांत्रिक तरीके से महानगर अध्यक्ष संजय छेत्री को हिरासत में ले लिया। पुलिस द्वारा खींचते हुए ले जाने के बावजूद कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद रहे और उन्होंने हाथ उठाकर लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। इस दमनकारी कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष संजय छेत्री ने हिरासत में से कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने आए थे। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, वह सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी के रहते निष्पक्ष चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें गिरफ्तार



कर सकते हैं, हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ लड़ेगा।

प्रदेश अध्यक्ष उमा गौड़ सिसौदिया ने कहा कि आज जो हुआ वह उत्तराखंड में लोकतंत्र के लिए काला दिन है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरह घसीट कर हिरासत में लिया गया, वह साबित करता है कि सरकार कितनी डरी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय जनता का कार्यालय है, भाजपा का कार्यालय नहीं। अगर हमारी मांग पर चुनाव

आयोग गौर नहीं करता तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में और तेज होगा। हम ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अडिग हैं।

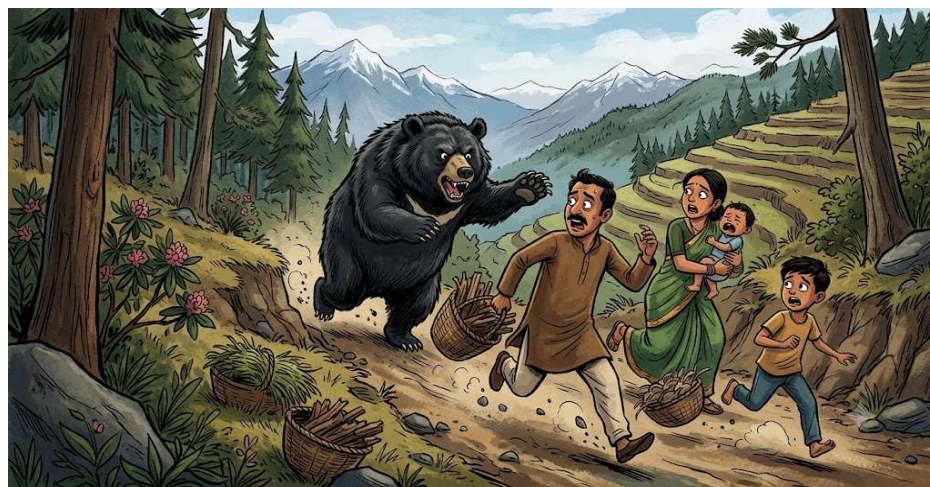
युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पुंडीर ने कहा युवा इस देश में वोट की चोरी और संस्थाओं के दुरुपयोग को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। छह नंबर पुलिया पर आज

पुलिस ने हमें रोकने की कोशिश की है, लेकिन यह लड़ाई अब हर गली-मोहल्ले तक जाएगी। युवा प्रकोष्ठ का हर कार्यकर्ता संजय छेत्री के साथ खड़ा है। हम पूछना चाहते हैं जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं रहेगा तो युवा किस पर भरोसा करेगा? ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना होगा।

भालू ने किया एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला!

हमारे संवाददाता
चमोली। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। ताजा मामला चमोली जिले के ज्योतिर्मठ नगर के सिंहधार वार्ड से सामने आया है, जहां आज तड़के एक भालू ने एक ही परिवार के चार लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। चारों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

जानकारी के आज सुबह करीब तीन बजे की है। बताया जा रहा है कि भालू सबसे पहले परिवार की गोशाला में घुसा और वहां मौजूद गाय पर हमला कर दिया। गाय को बचाने के लिए परिवार के सदस्य आगे आए, लेकिन भालू ने उन पर भी हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमले में परिवार के चार लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायलों की हालत गंभीर



होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया।

घटना के बाद सिंहधार वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हमले के बाद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी

है। लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। स्थानीय लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि जंगली जानवरों की आबादी वाले क्षेत्रों में आवाजाही लोगों के लिए खतरा बन रही है। ऐसे में

वन विभाग के सामने वन्यजीवों की सक्रियता पर निगरानी रखने और ग्रामीणों व शहरी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती है। उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष लंबे समय से गंभीर समस्या बना हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 से 31 जनवरी 2026 तक वन्यजीवों के हमलों में राज्य में 1,296 लोगों की मौत हुई, जबकि 6,624 लोग घायल हुए। मार्च 2026 की एक रिपोर्ट में सामने आए इन आंकड़ों की जानकारी उत्तराखंड विधानसभा में वन मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से दी गई थी। इसके अलावा, उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच वन्यजीवों से संबंधित घटनाओं में 55 लोगों की मौत और 407 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इन आंकड़ों को जोड़ने पर वर्ष 2000 से सितंबर 2026 तक वन्यजीवों से संबंधित घटनाओं में अनुमानित रूप से 1,351 लोगों की मौत और 7,031 लोगों के घायल होने का आंकड़ा सामने आता है। हालांकि, यह संयुक्त गणना अलग-अलग अवधि के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।

दून वैली मेल

संपादकीय

लोकतंत्र की आवाज पर पहरा

लोकतंत्र की खूबसूरती केवल चुनाव कराने और सरकारें बनाने में नहीं, बल्कि असहमति को सुनने और विरोध की आवाज को जगह देने में भी है। जब जनता की शिकायतें सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचतीं, जब जनप्रतिनिधियों के दरवाजे आम आदमी के लिए बंद नजर आते हैं और जब व्यवस्था से निराश लोग अपनी बात कहने के लिए सड़क पर उतरते हैं, तब धरना-प्रदर्शन लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाता है। ऐसे में यदि देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना देने के रास्ते सीमित होते हैं, तो सवाल केवल एक प्रदर्शन स्थल का नहीं, बल्कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का भी है। जंतर-मंतर लंबे समय से जन आंदोलनों, राजनीतिक विरोध और सामाजिक सरोकारों की आवाज का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां से उठने वाली आवाजें हमेशा सत्ता को पसंद आई हों, ऐसा नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की कसौटी ही यही है कि सत्ता अपने आलोचकों को कितनी जगह देती है। सरकार की नीतियों से असहमति रखने वाले नागरिक, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे संगठन और न्याय की मांग कर रहे लोग जब यहां जुटते हैं, तो वह केवल विरोध नहीं करते, बल्कि व्यवस्था को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराते हैं। हालांकि, यह भी सच है कि सार्वजनिक स्थलों पर धरना-प्रदर्शन के लिए नियमों की जरूरत होती है। राजधानी की सुरक्षा, यातायात, आम नागरिकों की सुविधा और सार्वजनिक व्यवस्था की अनदेखी नहीं की जा सकती। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार असीमित नहीं होता। लेकिन प्रतिबंधों और नियंत्रणों का औचित्य तभी स्वीकार्य हो सकता है, जब वह जरूरी, आनुपातिक, पारदर्शी और सभी पर समान रूप से लागू हों। व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर विरोध के अवसर ही सीमित कर दिए जाएं, तो यह चिंता का विषय बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नागरिक अपनी बात कहां रखें? संसद और विधानसभाएं जनप्रतिनिधियों के मंच हैं, लेकिन हर नागरिक को वहां सीधे अपनी शिकायत रखने का अवसर नहीं मिलता। सरकारी कार्यालयों में आवेदन और ज्ञापन देने की अपनी सीमाएं हैं। सामाजिक माध्यमों पर आवाज उठाने से संदेश तो फैल सकता है, लेकिन उससे हर बार शासन की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती। ऐसे में धरना-प्रदर्शन जनता के पास उपलब्ध शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक माध्यमों में से एक है। यदि इस माध्यम तक पहुंच कठिन बना दी जाए, तो असहमति व्यक्त करने के वैकल्पिक अवसर भी उपलब्ध कराने होंगे। यहां एक बुनियादी अंतर समझना जरूरी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन असहमति को दबाना उसका उद्देश्य नहीं हो सकता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक गतिविधियां एक जैसी नहीं हैं। यदि कुछ लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कुछ लोगों की गलतियों के आधार पर सभी प्रदर्शनकारियों के अधिकारों को संकुचित करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में विरोध की आवाज को सुनना शासन की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी परिपक्वता का प्रमाण है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, नीतियां बदलती रहती हैं और राजनीतिक दल सत्ता तथा विपक्ष की भूमिकाएं बदलते रहते हैं। आज जो दल सत्ता में है, कल उसे भी जनता के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विरोध के मंचों की उपयोगिता किसी एक राजनीतिक दल या विचारधारा तक सीमित नहीं है। यह मंच उन सभी के लिए जरूरी हैं, जो अपनी मांगों और शिकायतों को शांतिपूर्ण ढंग से सार्वजनिक करना चाहते हैं। जंतर-मंतर पर धरना देने को लेकर यदि कोई नया प्रतिबंध, न्यायिक निर्देश या प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है, तो उसकी वास्तविक प्रवृत्ति और सीमा को स्पष्ट करना भी आवश्यक है। क्या रोक पूरी तरह है, क्या केवल कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध है, या प्रदर्शन के लिए स्थान, समय और अनुमति से संबंधित नियम बदले गए हैं? इन सवालों के जवाब आधिकारिक आदेशों के आधार पर ही दिए जाने चाहिए। बिना पूरी जानकारी के इसे विरोध के अधिकार की समाप्ति कहना उतना ही अनुचित होगा, जितना हर प्रतिबंध को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेना। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। अनुमति देने की प्रक्रिया सरल हो, निर्णयों के आधार सार्वजनिक हों और किसी भी संगठन के साथ राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव न हो। यदि किसी स्थान पर प्रदर्शन संभव नहीं है, तो उचित विकल्प उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाना चाहिए। जंतर-मंतर का सवाल अंततः उस लोकतांत्रिक सोच का सवाल है, जिसमें सत्ता और जनता के बीच संवाद बना रहना चाहिए। लोकतंत्र में हर मांग स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन हर मांग को सुनने का अवसर देना उसकी जिम्मेदारी है। जनता को केवल मतदान के दिन याद करना और बाकी समय उसकी आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश करना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं हो सकता। देश की राजधानी में विरोध के मंच जितने सुलभ और व्यवस्थित होंगे, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। व्यवस्था के नाम पर खामोशी कायम करना आसान हो सकता है, लेकिन उससे असंतोष समाप्त नहीं होता। उसका समाधान संवाद, जवाबदेही और संवैधानिक अधिकारों के सम्मान में ही निहित है। लोकतंत्र में सरकार को विरोध से असुविधा हो सकती है, लेकिन विरोध का अधिकार ही समाप्त हो जाए, तो सत्ता से सवाल पूछने की गुंजाइश कहां बचेगी? जंतर-मंतर को लेकर किसी भी व्यवस्था की असली कसौटी यही होनी चाहिए कि सुरक्षा भी बनी रहे और जनता की आवाज भी सुनी जाती रहे।

दायित्वों की सौगात, चुनावी जिम्मेदारी

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2०27 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ भाजपा और धामी सरकार की सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक ओर सरकार लगातार दायित्वों का पिटारा खोलकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप रही है, तो दूसरी ओर दायित्वधारियों को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि जब सरकार में दायित्वों के जरिए नेताओं को राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तब उन्हीं चेहरों को चुनावी मोर्चे पर उतारने के पीछे संगठन की रणनीति क्या है? क्या यह चुनावी प्रबंधन को मजबूत करने की कवायद है या फिर पार्टी के भीतर राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास?

उत्तराखंड में भाजपा के सामने 2०27 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने, विधानसभा स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटी है। इसी क्रम में विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति और संगठनात्मक जिम्मेदारियों का बंटवारा अहम माना जा रहा है। लेकिन जब चुनावी जिम्मेदारियां ऐसे नेताओं को सौंपी जाती हैं, जो पहले से ही सरकार में दायित्व संभाल रहे हैं, तो इन नियुक्तियों के राजनीतिक संदेश पर चर्चा होना स्वाभाविक है।

प्रदेश में दायित्वों का वितरण भाजपा के लिए केवल प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं, बल्कि संगठन और सरकार

के बीच तालमेल बनाए रखने का माध्यम भी माना जाता है। लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव रखने वाले चेहरों और कार्यकर्ताओं को दायित्व देकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की जाती है। इससे पार्टी के भीतर असंतोष कम करने और नेताओं को संगठन से जोड़े रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि, दायित्वों के लगातार वितरण के बीच यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन पदों से सरकार को कितनी

◆**उत्तराखंड में धामी सरकार में लगातार बंट रही है कुर्सियां**
◆**दायित्वधारियों को विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाने पर सवाल**
◆**संगठन की रणनीति या सियासी संतुलन साधने की कवायद**

वास्तविक प्रशासनिक मदद मिल रही है और कितने दायित्व राजनीतिक प्रबंधन का हिस्सा बनकर रह गए हैं। यदि दायित्वधारी सरकारी जिम्मेदारियों के साथ चुनावी मोर्चे पर भी लगाए जाते हैं, तो उनकी प्राथमिकताओं और जवाबदेही को लेकर स्पष्टता जरूरी है।

दायित्वधारियों को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाए जाने के पीछे भाजपा की मंशा अपने अनुभवी नेताओं का उपयोग चुनावी प्रबंधन में करना हो सकती है। सरकार और संगठन के साथ काम करने का अनुभव रखने वाले नेता स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं की समस्याओं और क्षेत्रीय समीकरणों से परिचित होते हैं। ऐसे में पार्टी को उनसे चुनावी तैयारियों में लाभ मिलने की उम्मीद

हो सकती है। लेकिन इस रणनीति की सफलता केवल नियुक्तियों से तय नहीं होगी। चुनाव प्रभारी की भूमिका में विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक आकलन, संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, स्थानीय मुद्दों की पहचान और चुनावी रणनीति का प्रभावी क्रियान्वयन शामिल होता है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दायित्वधारी इन जिम्मेदारियों को कितना समय दे पाते हैं और उनके कामकाज का आकलन किस आधार पर किया जाता है।

दायित्वों के वितरण और चुनावी नियुक्तियों को लेकर विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का अवसर मिल सकता है। वह इसे राजनीतिक नियुक्तियों, पदों के वितरण और चुनावी लाभ के नजरिये से उठाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि, किसी नियुक्ति को केवल दायित्वधारी होने के आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता। असली सवाल नियुक्ति की प्रक्रिया, जिम्मेदारी की प्रवृत्ति, कार्यक्षमता और उसके परिणामों का है। यदि सरकार और संगठन इन नियुक्तियों के जरिए चुनावी प्रबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी दायित्वों का निर्वहन प्रभावित न हो। राजनीतिक जिम्मेदारी और सार्वजनिक पद की जवाबदेही के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना जरूरी है।

भाजपा के लिए 2०27 का चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में दायित्वों का वितरण,

▶▶ **शेष पृष्ठ 7 पर**

देहरादून की 4० सड़कों का जिम्मा निजी कंपनी के हवाले

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। राजधानी की सड़कों पर गड्ढे, उखड़ता डामर और बार-बार मरम्मत की समस्या से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक नया प्रयोग शुरू किया है। शहर की 4० प्रमुख सड़कों के रख-रखाव, सुधारीकरण और डामरीकरण की जिम्मेदारी अब सात साल के लिए एक निजी संस्था सरकारायास को सौंपी गई है। 1०2 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के लिए 89 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है। यह महज सड़क मरम्मत का ठेका नहीं, बल्कि राजधानी की सड़कों के रखरखाव की पूरी व्यवस्था बदलने की कोशिश है।

अब तक सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए अलग-अलग कार्यों पर टेंडर आमंत्रित किए जाते थे। इससे विभाग को बार-बार निविदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और मरम्मत के काम में समय लगने की शिकायतें सामने आती थीं। नए माडल में एक ही संस्था को लंबे समय तक सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी देकर जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई है। हालांकि, इस व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि सात साल तक सड़कों की गुणवत्ता कितनी बनी रहती है और जनता को गड्ढों से कितनी राहत मिलती है।

इस अनुबंध की सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी अवधि है। सामान्य तौर पर सड़क

निर्माण के बाद कुछ समय बीतते ही मरम्मत की जरूरत सामने आने लगती है। इसके बाद विभागीय प्रक्रिया, बजट और टेंडर के बीच काम अटकने की शिकायतें भी होती हैं। ऐसे में लंबे समय के रख-रखाव का अनुबंध संबंधित संस्था को सड़क की स्थिति बनाए रखने के लिए जवाबदेह बनाने का माध्यम बन सकता

◆**1०2 किलोमीटर सड़क नेटवर्क की देखरेख प्राइवेट हाथ में**
◆**गुणवत्ता बिगड़ी तो जवाबदेही तय करने का किया है दावा**

है। परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कान्ट्रैक्ट यानी प्रदर्शन आधारित रख-रखाव अनुबंध का मूल विचार यही है कि सड़क की देखरेख केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता पर भी ध्यान दिया जाए। हालांकि, इस माडल में भुगतान की शर्तें, गुणवत्ता के मानक, खराब सड़क पर दंड और अनुबंध उल्लंघन की कार्रवाई कितनी प्रभावी है, यह जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है।

1०2 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए 89 करोड़ रुपये का अनुबंध अपने आप में बड़ा वित्तीय दायित्व है। सात साल की अवधि के हिसाब से यह औसतन लगभग 12.71 करोड़ रुपये सालाना बैठता है। हालांकि, वास्तविक खर्च का आकलन अनुबंध की शर्तों, कार्यों के दायरे और भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया के आधार

पर ही किया जा सकता है। सवाल यह है कि इस राशि के बदले सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कौन-से मापदंड तय किए हैं? क्या सड़क की सतह, गड्ढों, जल निकासी और डामर की गुणवत्ता की नियमित जांच होगी? क्या नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा तय की गई है? इन बिंदुओं पर स्पष्ट व्यवस्था इस परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी होगी।

लॉनिवि के मुख्य अभियंता दयानंद के अनुसार, सड़कों की गुणवत्ता और निगरानी के लिए नेटवर्क सर्वे व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से सड़क नेटवर्क की स्थिति का आकलन कर रखरखाव की जरूरतों को पहचानने में मदद मिल सकती है। लेकिन तकनीक की उपलब्धता ही पर्याप्त नहीं है। सर्वे के निष्कर्षों का नियमित सार्वजनिक खुलासा, खराब सड़कों की पहचान और सुधार की समयसीमा भी तय होनी चाहिए। यदि निरीक्षण रिपोर्ट केवल विभागीय फाइलों तक सीमित रह गई, तो आम जनता के लिए यह जानना मुश्किल होगा कि 89 करोड़ रुपये के अनुबंध से वास्तव में कितना सुधार हुआ।

देहरादून में इस माडल को लागू करने के पीछे सड़क रख-रखाव की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की मंशा है। यदि यहां इसके परिणाम संतोषजनक रहते हैं,

▶▶ **शेष पृष्ठ 7 पर**

जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी टिहरी पैक्स-26 का समापन

नई टिहरी। भारतीय डाक विभाग के डाक मंडल टिहरी की ओर से राजकीय महाविद्यालय के बहुद्देशीय सभाग में जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी टिहरी पैक्स-26 का समापन हो गया। इस अवसर पर उत्तराखंड परिमंडल के डाक निदेशक दिनेश कुमार मिस्त्री तथा डाक विभाग के अधिकारियों ने बूढ़ाकेदार मंदिर के डाक टिकट का अनावरण किया। डाक अधीक्षक गंगा सिंह राणा ने कहा कि डाक विभाग अपनी सेवाओं को तक दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों की जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगा। कहा कि प्रदर्शनी में डाक टिकटों के माध्यम से डाक विभाग के कर्मियों ने छात्र-छात्राओं और लोगों को भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला विरासत और ज्ञान विज्ञान के पहलुओं के बारे में जानकारी दी। डाक विभाग के अधिकारियों ने दो दिवसीय प्रदर्शनी में छात्र-छात्राओं के बीच संपन्न हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अधीक्षक राणा ने कहा कि डाक टिकट प्रदर्शनी से फिलेटली के प्रचार-प्रसार को नई दिशा मिली है।

कक्ष सेवक नीले, पर्यावरण मित्र हरे एप्रन में आएंगे नजर

श्रीनगर गढ़वाल (आरएनएस)। उपजिला चिकित्सालय श्रीनगर में अब कक्ष सेवक और पर्यावरण मित्र अलग-अलग रंगों के एप्रन में नजर आएंगे। अस्पताल प्रशासन ने कर्मचारियों की पहचान आसान बनाने और व्यवस्था में सुधार के लिए यह पहल की है। सोमवार से कक्ष सेवक नीले और पर्यावरण मित्र हरे रंग के एप्रन में ड्यूटी करते दिखाई देंगे। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रचित गर्ग ने बताया कि अस्पताल में कार्यरत 17 कक्ष सेवकों और 11 पर्यावरण मित्रों को एप्रन वितरित किए गए हैं। अलग-अलग रंग के एप्रन से मरीजों और तीमारदारों को संबंधित कर्मचारियों की पहचान करने में आसानी होगी। साथ ही अस्पताल में स्वच्छता, अनुशासन और व्यवस्थित कार्य वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान निर्धारित रंग का एप्रन पहनने और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

बंगापानी में वन्यजीव संरक्षण के बारे में बताया

पिथौरागढ़ (आरएनएस)। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की ओर से सीमांत में सात दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदि कैलास, कुटी, गुंजी सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर जानकारी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. के.एस. कनवाल, डॉ. शिवपाल, दीपक चंद्र तिवारी, प्रकाश सिंह, बंटी राणा, गोविंद सिंह बिष्ट शामिल रहे। पीएमश्री जीआईसी कनार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीते दिन डॉ. लक्ष्मण सिंह, जितेंद्र सिंह, अभिनव वर्मा व मंजुल नौटियाल ने विद्यार्थियों व स्थानीय लोगों को वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता व मानव-वन्यजीव संघर्ष के बारे में जानकारी दी।

अक्षय कुमार के पुतले ने मारी बाजी, दशहरा महोत्सव के कलाकार सम्मानित

अल्मोड़ा (आरएनएस)। नगर निगम सभागार में दशहरा महोत्सव समिति की ओर से आयोजित समारोह में दशहरा महोत्सव 2025 के विजेता पुतलों के कलाकारों और आयोजन में योगदान देने वालों को सम्मानित किया गया। अक्षय कुमार के पुतले ने प्रथम स्थान हासिल कर 15 हजार रुपये का पुरस्कार जीता। नौरातक का पुतला दूसरे स्थान पर रहा, जिसे 11 हजार रुपये, जबकि रावण के पुतले को तीसरे स्थान पर 7,500 रुपये दिए गए। मुख्य अतिथि विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा का दशहरा महोत्सव शहर की सांस्कृतिक पहचान है और इससे स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है। उन्होंने शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले और जीजीआईसी मैदान के लंबित कार्य के समाधान के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। महापौर अजय वर्मा ने आयोजन को बेहतर बनाने में नगर निगम के सहयोग की बात कही। समिति के मुख्य संयोजक धर्मेन्द्र बिष्ट ने पुतला दहन के लिए स्थायी स्थान निर्धारित करने और शत्रु संपत्ति से संबंधित स्थान को सांस्कृतिक आयोजनों के लिए विकसित करने की मांग उठाई। समिति अध्यक्ष अजीत सिंह कार्की ने नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और आयोजन में अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया। पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रकाश जोशी ने दशहरा महोत्सव की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले पुराने कलाकारों के योगदान को याद किया। समारोह में समिति पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सदस्यों ने भाग लिया।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञा पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आखिरी हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो सांध्य दैनिक दून वैली मेल के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

‘हैट्रिक’ के लिए भाजपा का ‘मास्टर प्लान’

कार्यालय संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि सत्ता विरोधी रझानों, बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत बनाए रखने की भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने, शक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बहुस्तरीय रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

भाजपा की रणनीति का मूल मंत्र साफ है कि चुनाव की तैयारी चुनावी घोषणा के बाद नहीं, बल्कि उससे काफी पहले शुरू होनी चाहिए। पार्टी संगठन को जितना अधिक सक्रिय और चुनावी दृष्टि से तैयार रखा जाएगा, मतदान के समय उसका लाभ मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। इसी सोच के तहत विस्तारक योजना को अहम माना जा रहा है। संगठन के भीतर जिम्मेदारियों का बंटवारा, क्षेत्रवार समन्वय और बूथों पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना इस अभियान के प्रमुख हिस्से हैं। भाजपा की चुनावी राजनीति में बूथ प्रबंधन लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पार्टी अब इसी माडल को और प्रभावी बनाने की कोशिश में है। शक्ति केंद्रों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, मतदाताओं से निरंतर संपर्क बनाए रखना और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना इस रणनीति के प्रमुख बिंदु हैं।

पार्टी की कोशिश है कि चुनाव के समय संगठन अचानक सक्रिय होने के बजाय पूरे साल जनता के बीच मौजूद रहे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को क्षेत्रवार जिम्मेदारी देना और संगठनात्मक गतिविधियों की नियमित समीक्षा करना महत्वपूर्ण होगा। भाजपा जानती है कि विधानसभा चुनाव में प्रदेशव्यापी मुद्दों के साथ स्थानीय समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बूथ स्तर पर कमजोर कड़ियों की पहचान और उनका समाधान पार्टी की प्राथमिकता बन सकता

है। भाजपा की विस्तारक योजना को चुनावी तैयारी के महत्वपूर्ण औजार के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश स्तर पर संयोजकों और सह-संयोजकों की जिम्मेदारी तय करने का उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों में



◆2027 की जंग को संगठन से बूथ तक चुनावी विसात बिछाने में जुटी भाजपा
◆शक्ति केंद्रों की मजबूती, सरकार की उपलब्धियों से सत्ता में वापसी का लक्ष्य
◆उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ तेज की तैयारियां

समन्वय बढ़ाना और पार्टी की रणनीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है।

इस योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि संगठन की योजनाएं कागजों से निकलकर मतदाताओं के बीच कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती हैं। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व के बीच तालमेल और जनता की समस्याओं पर त्वरित प्रतिक्रिया ही इस रणनीति की वास्तविक सफलता तय करेगी। केवल बैठकों और संगठनात्मक घोषणाओं से चुनावी माहौल नहीं बनता। इसके लिए जनता के बीच निरंतर संवाद जरूरी है। भाजपा की तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का प्रदर्शन होगा। पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और अपने राजनीतिक एजेंडे को चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाना चाहेगी। लेकिन चुनाव में उपलब्धियों का प्रचार तभी प्रभावी होगा, जब मतदाता उन्हें अपने जीवन में महसूस भी करें।

रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसे मुद्दे उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण बने हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। भाजपा के सामने चुनौती होगी कि वह इन सवालों पर ठोस जवाब दे और सरकार के कामकाज को लेकर उठने वाली

आलोचनाओं का तथ्यात्मक ढंग से सामना करे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर जीत का गणित केवल प्रदेश नेतृत्व के चेहरे से तय नहीं होगा। उम्मीदवारों की स्वीकार्यता, स्थानीय गुटबाजी, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण तथा मौजूदा विधायकों के प्रति जनता का रुख भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करेगा। ऐसे में टिकट वितरण भाजपा के लिए सबसे संवेदनशील चरणों में से एक हो सकता है।

भाजपा की चुनावी रणनीति के सामने कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। यदि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार के आरोपों और क्षेत्रीय विकास के सवालों को लेकर प्रभावी अभियान खड़ा करती है, तो मुकाबला कई सीटों पर कड़ा हो सकता है। विपक्ष की एकजुटता, स्थानीय नेतृत्व का तालमेल और उम्मीदवारों का चयन चुनावी परिणामों पर असर डालेंगे। भाजपा के लिए चुनौती केवल अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की नहीं, बल्कि उन मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने की भी होगी, जो सरकार के कामकाज का आकलन स्थानीय अनुभवों के आधार पर करते हैं। वहीं कांग्रेस के सामने इन असंतोषों को वोट में बदलने और संगठनात्मक कमजोरी से पार पाने की चुनौती रहेगी।

भाजपा की तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी यह संकेत देती है कि पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर संगठनात्मक स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। बूथ प्रबंधन, विस्तारक योजना, शक्ति केंद्रों की सक्रियता और सरकार की उपलब्धियों का प्रचार उसके चुनावी अभियान के प्रमुख आधार बन सकते हैं। हालांकि, चुनावी रणनीति की असली परीक्षा जनता के बीच होगी। संगठन की मजबूती तभी परिणाम देगी, जब वह मतदाताओं की अपेक्षाओं और समस्याओं से जुड़ सके। भाजपा के लिए हैट्रिक का रास्ता संगठनात्मक ताकत के साथ-साथ सरकार के कामकाज, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और स्थानीय मुद्दों के समाधान से होकर गुजरेगा। 2027 में भाजपा की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वह अपने संगठनात्मक आत्मविश्वास को जनता के भरोसे में कितना बदल पाती है। हैट्रिक का लक्ष्य तय करना एक बात है, लेकिन उत्तराखंड की जनता से तीसरी बार जनादेश हासिल करना दूसरी।

किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार: लाडी

रुद्रपुर (आरएनएस)। ओलावृष्टि से धान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से प्रभावित किसानों को 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही सहकारी समितियों और बैंकों से लिए गए कृषि ऋण माफ करने तथा बिजली बिलों में राहत देने की मांग उठाई है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हेरन्द सिंह लाडी ने चेतावनी दी कि दो दिन के भीतर मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा। रुद्रपुर सिटी क्लब में प्रेसवार्ता के दौरान लाडी ने कहा कि जिले के किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद शुरू कराने के लिए लगातार धरना-प्रदर्शन करते रहे, लेकिन सरकार

समय पर खरीद शुरू नहीं करा पाई। इससे किसानों का धान खेतों में पड़ा रहा और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीद की उचित नीति नहीं होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ीं। ऐसे में सरकार को फसल नुकसान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ 50 हजार रुपये मुआवजा देना चाहिए। लाडी ने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई किसानों के बच्चों की शादी होनी है और उन्हें ट्रैक्टर की किस्तें भी चुकानी हैं। ऐसे में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने सहकारी समितियों और बैंकों से लिए गए कृषि ऋणों के साथ ही बिजली के बिल माफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बाजपुर में हेलीकॉप्टर

उतारकर प्रभावित खेतों का सर्वे किया, लेकिन किसानों के मुआवजे को लेकर कोई घोषणा नहीं की। अब छह हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की बात सामने आ रही है। किसान कांग्रेस इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान के अनुपात में राहत दी जानी चाहिए। लाडी ने बताया कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे सोनिया होटल में किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी किसानों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सम्मेलन में शामिल होने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा, पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल और संदीप चीमा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

अपने बच्चे में छिपी प्रतिभा पहचानना चाहते हैं? इन तरीकों को अपनाएं

हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी खासियत को पहचानें और उसे निखारें। बच्चों में छिपी प्रतिभा को पहचानना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन सही दिशा-निर्देश और प्रयासों से यह संभव है। इस लेख में हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे की खासियत को पहचान सकते हैं और उसे विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इससे आपका बच्चा आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकेगा।

बच्चों की रुचियों का करें अवलोकन : बच्चों की रुचियों का अवलोकन करना बहुत जरूरी है। उन्हें अलग-अलग गतिविधियों में शामिल करें, जैसे कला, संगीत, खेल या विज्ञान। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन-सी गतिविधि में उनका मन लगता है और वे किस चीज में ज्यादा आनंद लेते हैं। उनके साथ समय बिताकर उनकी पसंदीदा गतिविधियों पर चर्चा करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। इससे आप उनके जुनून को समझ सकेंगे और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकेंगे।

खेल-कूद में भागीदारी बढ़ाएं : खेल-कूद बच्चों के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि यह उनकी मानसिक और शारीरिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। अलग-अलग खेलों में भाग लेकर बच्चे टीमवर्क, अनुशासन और समर्पण जैसी जरूरी बातें सीखते हैं। इसके अलावा खेल-कूद से उनकी शारीरिक फिटनेस भी बनी रहती है। बच्चों को अलग-अलग खेलों का अनुभव कराने से उनकी रुचियां और क्षमताएं खुलकर सामने आती हैं, जिससे आप उनकी प्रतिभा को पहचान सकते हैं।

पढ़ाई के साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों पर दें ध्यान : पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान देना भी अहम है। संगीत, डांस, पेंटिंग या लेखन जैसी गतिविधियां बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं और उनकी सोचने की क्षमता को विकसित करती हैं। इन गतिविधियों से बच्चे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और उनकी आत्मविश्वास भी बढ़ती है। इसके अलावा रचनात्मक गतिविधियों से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।

तकनीकी ज्ञान दें अहमियत : आजकल तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी हो गया है। बच्चों को कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल फोन का सही उपयोग सिखाना चाहिए। प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग जैसी तकनीकी गतिविधियां उनके भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इससे वे नई चीजें सीखते हैं और उनकी समस्या समाधान करने की क्षमता भी बढ़ती है। तकनीकी ज्ञान से बच्चे न केवल आज की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में भी सफल हो सकते हैं।

सामाजिक गतिविधियों में करें भागीदारी : सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना बच्चों को मिलनसार बनाता है और उनकी बातचीत की क्षमता को सुधारता है। स्कूल, क्लब या समाज सेवा जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर बच्चे नए दोस्त बनाते हैं, अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और दूसरों की मदद करना सीखते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाजिक रूप से जागरूक होते हैं।

सर्दी-जुखाम होने पर नहीं आता किसी चीज का स्वाद? आजमाएं ये असरदार सुझाव

सर्दी-जुखाम एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जो नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह आपको बहुत कमजोर महसूस कराती है। इसके चलते आपको खाना खाने का मन नहीं करता और अगर आप कुछ खाते भी हैं तो उसका स्वाद भी ठीक से महसूस नहीं होता। आइए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे, जिन्हें आजमाकर सर्दी-जुखाम के दौरान बिना स्वाद के भी खाना खाने का मन बना सकते हैं।

अदरक का करें सेवन : अदरक में ऐसे गुण होते हैं, जो गले और नाक की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही अदरक ताजगी का एहसास दिला सकती है। लाभ के लिए अदरक की चाय बनाकर पिएं या फिर अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े पर शहद डालकर खाएं। अदरक के सेवन से अन्य लाभ भी मिल सकते हैं। इसके सेवन से गले का दर्द ठीक हो सकता है, खराश दूर हो सकती है और राहत मिल सकती है।

पिएं नींबू पानी : नींबू में विटामिन-सी होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर सर्दी-जुखाम के लक्षणों से राहत दिला सकता है। इसके अलावा नींबू पानी पीने से गले की खराश और नाक के बंद होने की समस्या भी दूर हो सकती है। लाभ के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसका सेवन करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। आप इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं।

लहसुन को डाइट में करें शामिल : लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं, जो सर्दी-जुखाम के कारण शरीर में हुई सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन का सेवन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर सर्दी-जुखाम के कारण होने वाली समस्याओं से राहत दिला सकता है। लाभ के लिए लहसुन की कली को बारीक काटकर एक गिलास पानी में मिलाएं और उसका सेवन करें। इसे व्यंजनों में शामिल करना भी एक अच्छा तरीका है।

शहद और दालचीनी का मिश्रण बनाकर खाएं : दालचीनी में ऐसे गुण होते हैं, जो गले की खराश को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर सर्दी-जुखाम के कारण होने वाली समस्याओं से राहत दिला सकती है। लाभ के लिए एक चम्मच शहद में थोड़ी दालचीनी पाउडर मिलाकर खाएं। दालचीनी के अन्य फायदे भी हो सकते हैं।

छाती में जकड़न से राहत पाने के लिए अपनाएं घरेलू नुस्खे

देश के कई इलाकों में बारिश का मौसम है। ऐसे में मौसमी बुखार, खांसी, सर्दी और फ्लू जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे छाती में अकसर जकड़न और बलगम का जमाव हो जाता है। इससे खांसी आती है और सांस लेते समय घरघराहट की आवाज का अनुभव होता है। इससे राहत पाने के लिए दवाइयों की बजाय प्राकृतिक और घरेलू उपचार का विकल्प चुनें। विलिए फिर आज इसी से जुड़े असरदार घरेलू नुस्खे जानते हैं।

अदरक

अदरक एक प्राकृतिक डिक्ॉन्जेस्टेंट के रूप में काम करता है और यह अतिरिक्त बलगम संचय को साफ करके फेफड़ों को आराम पहुंचाता है। लाभ के लिए अदरक का एक छोटा टुकड़ा चबाएं या उबलते पानी में इस मसाले के कुछ टुकड़े डालकर अदरक की चाय बनाएं। इस चाय के सेवन से आपको ये फायदे भी मिलते हैं। आप चाहें तो ताजे अदरक के रस को कुचले हुए तुलसी की पत्तियों और शहद के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं।

हल्दी

हल्दी भी छाती में बलगम के जमाव से राहत दिलाने और आपको बेहतर सांस लेने में मदद करती है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और यह फेफड़ों में सूजन को प्रबंधित करने में मदद करती है। लाभ के लिए उबलते पानी में हल्दी पाउडर, काली मिर्च और शहद मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को पी लें। कई औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी से ये फायदे भी मिलते हैं।



नींबू

नींबू विटामिन- सी से भरपूर होता है, जो न केवल प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बल्कि वायुमार्ग में सूजन को कम करने के लिए भी उपयोगी है। लाभ के लिए शहद के साथ थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं और फिर पूरे दिन नियमित अंतराल पर एक बड़ी चम्मच इस मिश्रण का सेवन करें। इससे नुस्खे से खांसी, बंद नाक और गले और फेफड़ों में जलन से तुरंत राहत मिल सकती है।

थाइम

थाइम में फ्लेवोनोइड्स होते हैं, जो सूजन को कम कर सकते हैं, फेफड़ों की मांसपेशियों को शांत कर सकते हैं और ठीक से सांस लेने के लिए बंद वायुमार्ग को खोल सकते हैं। इसमें एंटी-स्पास्मोडिक,

एक्सपेक्टोरेंट (बलगम को बाहर निकालने वाला) और एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो बलगम को कम कर सकते हैं। लाभ के लिए आप थाइम की चाय बनाकर पी लें या फिर इसके एसेंशियल ऑयल को गर्म पानी में मिलाकर इससे गरारे करें।

भाप लें

छाती में बलगम के जमाव से राहत पाने के लिए भाप लेना काफी मददगार है। अध्ययनों के मुताबिक, गर्म पानी से नहाने या गर्म पानी से भरे बर्तन से भाप लेने से बलगम पतला हो जाता है, जिससे यह आसानी से निकल जाता है। यह खांसी, सर्दी और बंद वायुमार्ग से राहत दिला सकता है। बेहतर परिणामों के लिए आप उबलते पानी में नीलगिरी का तेल भी मिला सकते हैं।

माइग्रेन के कारण पेटदर्द की हो सकती है समस्या

क्या आपको पता है कि माइग्रेन के कारण पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है। जी हां, माइग्रेन सिर्फ सिर में ही नहीं, बल्कि पेट में भी हो सकता है। पेट में होने वाले माइग्रेन को ऐब्डॉमिनल माइग्रेन कहते हैं और इसकी वजह से आपको तेज दर्द, मरोड़, थकान और उल्टी हो सकती है। पेट का माइग्रेन आमतौर पर अनुवांशिक होता है और छोटे बच्चों को होता है। इसका सबसे

ज्यादा खतरा उन बच्चों को होता है जिनके माता-पिता पहले से माइग्रेन के शिकार हैं। बच्चों में भी इस तरह के माइग्रेन के मामले सबसे ज्यादा लड़कियों में देखे गए हैं। जिन बच्चों को बचपन में ऐब्डॉमिनल माइग्रेन की शिकायत होती है, बड़े होकर उन्हें सिर का माइग्रेन होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। ऐब्डॉमिनल माइग्रेन के सही-सही कारण का अब तक पता नहीं लगा है,

लेकिन डॉक्टर मानते हैं कि शरीर में बनने वाले दो कंपाउंड हिस्टामाइन और सेरोटोनिन इस तरह के दर्द के जिम्मेदार होते हैं। शरीर में ये दोनों ही कंपाउंड ज्यादा चिंता करने और अवसाद के कारण बनते हैं। चाइनीज फूड्स और इंस्टैंट नूडल्स में इस्तेमाल होने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट या एमएसजी, प्रोसेस्ड मीट और चॉकलेट के ज्यादा सेवन से भी शरीर में ये कंपाउंड बनते हैं।

शब्द सामर्थ्य -054

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. आय व्यय का लेखा-जोखा, गणित, एकाउंट 3. विनती, अदब 6. दृष्टांत, सुपुर्दगी, उदाहरण 7. मूल्यवान, बहुमूल्य 8. अच्छे ढंग में गाया जाने वाला सुंदर गीत 10. बराबर, सम 12. मुख, चेहरा 14. अनुकृति, अनुकरण, असल का विलोम 17. दिमाग,

मस्तिष्क 18. मनोहर, सुंदर, इच्छित, प्यारा 19. गर्मी, ताप 21. रसिया, प्रेमी, रसपान करने वाला 23. दबाव, भार 24. भीख 25. काम से जी चुराने वाला, आलसी।

ऊपर से नीचे

1. साहस, वीरता, बहादुरी 2. बहिन, प्रवाहित होना 3. प्रणय क्रीडा, सुखोपभोग, हावभाव

4. विश्वास, प्रतीति 5. इंतजार 9. खाने-पीने का सामान, रसद 11. नशीला, मदभरा 12. घायल, जखमी 13. झुकना, प्रणाम, नमस्कार 14. दृष्टि, निगाह 15. तीव्रइच्छा 16. अर्थ, अभिप्राय, स्वार्थ 20. इम्तिहान, योग्यता आदि को परखना 22. जुल्म, अन्याय 23. पत्नी, बीवी, एक प्रत्यय।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 53 का हल

दा	ढ़ी		की		खा	सो	आ	म
वा		त	म	त्रा			जा	
न	जा	क	त		बा	अ	द	ब
ल		ली		वि	ला	प		हा
	अ	फ	सा	ना		मा	हि	र
दा	ब			श	गु	न		
न		उ	प	का	र		शि	
व		त्स		र		त	क	ला
	सा	व	न		गु	रु	वा	र

जैकी श्रॉफ-शरद केलकर की हॉरर फिल्म काली खेती 23 अक्टूबर को होगी रिलीज

अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अब तक एक्शन, रोमांच और हास्य फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया है। अब वह पहली बार डरावनी फिल्म में नजर आने वाले हैं। पिछले साल घोषित की गई उनकी इस फिल्म का आधिकारिक नाम काली खेती' रखा गया है। फिल्म में अभिनेता शरद केलकर भी प्रमुख भूमिका में दिखाई देंगे। निर्माताओं ने अब इसकी प्रदर्शन तिथि की घोषणा कर दी है।

हारिस इम्टियाज खान के लेखन और निर्देशन में बनी काली खेती' ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित डरावनी फिल्म है। इसका निर्माण सना खान ने ब्लैककैनवास स्टूडियो के बैनर तले किया है। फिल्म में नेहा सरगम मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में नजर आएंगी। निर्माताओं ने फिल्म का नया चलचित्र पोस्टर जारी किया है, जिसमें इसकी भयावह और रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाई गई है। पोस्टर के साथ सुनाई देने वाली डरावनी ध्वनि फिल्म के रहस्य और रोमांच को और गहरा करती है। इससे पहले जून 2026 में भी फिल्म का चलचित्र पोस्टर जारी किया गया था। काली खेती' को लेकर जैकी श्रॉफ के प्रशंसकों में खासा उत्साह है, क्योंकि यह उनके करियर की पहली डरावनी फिल्म होगी। फिल्म की ग्रामीण पृष्ठभूमि और रहस्यमयी कहानी दर्शकों के लिए कुछ अलग अनुभव पेश करने का दावा करती है। यह फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। इसी दिन लव रंजन की फिल्म पहला प्यार दूसरी बार' भी रिलीज होने जा रही है। ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच सिनेमाघरों में दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी।

आयुष्मान और शरवरी ने किया डाडिया-गरबा!

फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या की बहुप्रतीक्षित फिल्म ये प्रेम मोल लिया' इस साल 27 नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के लिए तैयार है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। दोनों की नई जोड़ी को लेकर दर्शकों में पहले से ही उत्सुकता बनी हुई है। फिल्म के शीर्षक गीत ये प्रेम मोल लिया' के बाद अब निर्माताओं ने इसका नया गीत जय अंबे बोल' जारी किया है।

जय अंबे बोल' मां दुर्गा को समर्पित भक्तिमय गीत है। इस गीत को हिमेश रेशमिया ने अपनी आवाज दी है और संगीत भी तैयार किया है। गीत में आयुष्मान खुराना और शरवरी डाडिया-गरबा करते नजर आ रहे हैं। नवरात्रि से पहले जारी किया गया यह गीत उत्सव और भक्ति के रंग को दर्शाता है। फिल्म के शीर्षक गीत को भी दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसे वीडियो साझा करने वाले मंच यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है। नए गीत के साथ फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ने की उम्मीद है। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी ये प्रेम मोल लिया' एक पारिवारिक नाट्य फिल्म है। फिल्म का निर्माण राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी की जोड़ी पहली बार पर्दे पर साथ दिखाई देगी। फिल्म 27 नवंबर, 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।

विक्रम प्रभु की 26वीं फिल्म का नाम सिटी ऑफ गोल्ड', सोने की तस्करी की रहस्यमयी दुनिया दिखाएगी फिल्म

अभिनेता विक्रम प्रभु की आगामी 26वीं फिल्म का आधिकारिक नाम सिटी ऑफ गोल्ड' रखा गया है। पहली बार निर्देशन की कमान संभाल रहे सिद्धार्थ के निर्देशन में बन रही यह अपराध और रोमांच पर आधारित फिल्म है। इसमें शिवात्मिका राजशेखर मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में नजर आएंगी। उनके साथ राहुल और अमला शाजी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म का निर्माण राहुल रोमियो पिक्चर्स' के बैनर तले कर रहे हैं। फिल्म के नाम और प्रथम झलक हाल ही में जारी की गई है, जिसके बाद दर्शकों में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। प्रथम झलक में विक्रम प्रभु सोने की ईंटों को बेहद सहजता से संभालते नजर आते हैं। उनके चेहरे के गंभीर भाव फिल्म की कहानी में छिपी सोने की दुनिया और उससे जुड़े रहस्यमयी अपराध जगत की ओर संकेत करते हैं। फिल्म की झलक में कोयंबटूर से जुड़े सोने की तस्करी के एक बड़े अभियान की झलक दिखाई गई है। इसमें अधिकारियों, कारोबारियों और कई रहस्यमयी किरदारों को शामिल किया गया है। हालांकि, फिल्म में होने वाले मुख्य टकराव और कहानी के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को फिलहाल पर्दे के पीछे रखा गया है। इससे फिल्म की कहानी को लेकर रहस्य और बढ़ गया है।

सिटी ऑफ गोल्ड' सोने के व्यापार और उसकी तस्करी की उस छिपी हुई दुनिया को सामने लाने का प्रयास करती है, जो आम तौर पर चमक-दमक से भरे बाजार के पीछे दिखाई नहीं देती। फिल्म में इस कारोबार से जुड़े लोगों, उनके हितों और घटनाओं पर केंद्रित कहानी पेश की जाएगी। फिल्म की तकनीकी टीम में दक्षिण भारतीय सिनेमा के कई चर्चित नाम शामिल हैं। युवन शंकर राजा ने फिल्म का संगीत तैयार किया है, जबकि कार्तिक शरज ने छायांकन की जिम्मेदारी संभाली है। अरुल मोसेस ए फिल्म के संपादन का काम देख रहे हैं। हरि हरन पीएस फिल्म के कला निर्देशक हैं, जबकि काव्या वेलुसामी ने वेशभूषा की जिम्मेदारी संभाली है। फिल्म के मारधाड़ वाले दृश्यों की संरचना और निर्देशन दिनेश कासी ने किया है। कलाकारों की टीम में जीएम सुंदर, सुनील सुखदा सहित कई अन्य कलाकार भी शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, सिटी ऑफ गोल्ड' की शूटिंग कोयंबटूर, चेन्नई और केरल के विभिन्न स्थानों पर की गई है। फिलहाल फिल्म की प्रदर्शन तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

काँप के किरदार में नजर आएंगी शीना चौहान!

अभिनेत्री शीना चौहान की तेलुगु साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म जातस्य मरणं ध्रुवम् रिलीज के लिए लेकर तैयार है। अभिनेत्री ने फिल्म में काँप की भूमिका अदा करने का अनुभव शेयर किया। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की शूटिंग से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें उनके साथ अभिनेता जेडी चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं। अभिनेत्री ने तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, जातस्य मरणं ध्रुवम् शूटिंग के दौरान जेडी चक्रवर्ती के साथ एक स्पेशल पल। कुछ किरदार कैमरा बंद होने के बाद भी आपके साथ रह जाते हैं। आईपीएस ऑफिसर और काँप का किरदार निभाना बहुत ही शानदार रहा! आप सब क्या देखने वाले हैं, इसके लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकती।

श्रवण जोन्नादा द्वारा निर्देशित फिल्म का शीर्षक भगवद्गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक से प्रेरित है, जिसका अर्थ है जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और संगीत मशहूर संगीतकार गिब्रान ने तैयार किया है जबकि फिल्म का निर्माण सुलक्ष एंटरटेनमेंट मीडिया के बैनर तले मलकापुरम शिव कुमार कर रहे हैं।

फिल्म में अभिनेत्री शीना चौहान के साथ जेडी चक्रवर्ती, नरेश अगस्त्य, सीरत कपूर, शीना चौहान, प्रीति जंघियानी, हितेन तेजवानी और राजेश शर्मा जैसे उम्दा कलाकार नजर आएंगे। फिल्म में जेडी



चक्रवर्ती एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अभिनेत्री शीना चौहान उनकी असिस्टेंट पुलिस अधिकारी अनुषा के रोल में एक्शन और मार्शल आर्ट्स का दम दिखाती नजर आएंगी।

यह फिल्म रहस्य, सस्पेंस, अप्रत्याशित ट्विस्ट, फॉरेंसिक सुरागों और मानसिक माइंड गेम्स से भरपूर एक गहन खोजी कहानी है। फिल्म की कहानी एक मर्डर के ईर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें दर्शकों को चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।

यह फिल्म तेलुगु भाषा के साथ-साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में पैन-इंडिया स्तर पर रिलीज के लिए तैयार की गई है। तेलुगु थ्रिलर फिल्म जातस्य मरणं ध्रुवम् अक्टूबर 2026 के बीच सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए निर्धारित की गई है। फिल्म के निर्देशक श्रवण जोन्नादा ने हाल ही में पुष्टि की है कि वे इस अवधि के दौरान एक बड़े पैमाने पर फिल्म को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।

दो हिस्सों में आएंगी जूनियर एनटीआर की ड्रैगन'!



जूनियर एनटीआर और निर्देशक प्रशांत नील की बहुप्रतीक्षित फिल्म ड्रैगन' को लेकर नई जानकारी सामने आई है। खबरों के मुताबिक, फिल्म को दो हिस्सों में बनने वाली एक बड़े पैमाने की एक्शन गाथा के रूप में तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों हिस्सों की शूटिंग साथ-साथ की जा रही है और निर्माताओं की कोशिश है कि दोनों फिल्मों की रिलीज के बीच ज्यादा लंबा अंतर न रहे। फिल्म का पहला भाग आधिकारिक रूप से 11 जून 2027 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगा। हालांकि, दूसरे भाग की रिलीज तारीख की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

रिपोर्टों के अनुसार, ड्रैगन' की शुरुआत एक ही फिल्म के रूप में की गई थी, लेकिन कहानी के व्यापक आकार और निर्माण योजना को देखते हुए बाद में इसे दो हिस्सों में बनाने का फैसला किया गया। फिल्मफेयर' की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की कहानी को बड़े स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए निर्माण योजना में बदलाव किया गया।

फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स मिलकर कर रहे हैं। इसे बड़े स्तर की अखिल भारतीय फिल्म के रूप में तैयार किया जा रहा है। टी-सीरीज फिल्म को कई भाषाओं में दर्शकों

तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालेगा।

फिल्म की आधिकारिक पहली झलक से संकेत मिलता है कि ड्रैगन' की कहानी वर्ष 1967 के दौर में स्थापित है। फिल्म में अंतरराष्ट्रीय अफीम कारोबार की पृष्ठभूमि दिखाई जाएगी, जिसमें अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी से जुड़े घटनाक्रम कहानी का हिस्सा बताए जा रहे हैं।

जूनियर एनटीआर फिल्म में लूगर' नाम का किरदार निभा रहे हैं। वहीं, रुक्मिणी वसंत महिला मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में अनिल कपूर, बीजू मेनन और आशुतोष राणा भी महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में दिखाई देंगे।

ड्रैगन' का निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी रवि बसरूर ने संभाली है, जबकि छायांकन भुवन गौड़ कर रहे हैं। फिल्म का संपादन प्रणव श्री प्रसाद कर रहे हैं।

फिल्म की आधिकारिक झलक के साथ इसके पहले भाग की रिलीज तारीख 11 जून 2027 तय की जा चुकी है। हालांकि, दोनों हिस्सों की शूटिंग को लेकर चल रही खबरों के बावजूद दूसरे भाग के प्रदर्शन की तारीख और विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में निर्माताओं की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की जोड़ी के कारण ड्रैगन' को लेकर पहले से ही दर्शकों में काफी उत्सुकता है। फिल्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अंतरराष्ट्रीय अपराध जगत और बड़े स्तर के एक्शन को देखते हुए इसे आने वाली प्रमुख अखिल भारतीय फिल्मों में शामिल किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद सड़कों की हालत खराब

□आखिर अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा: लालचंद शर्मा

हमारे संवाददाता
देहरादून। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने देहरादून शहर की बदहाल सड़कों को लेकर प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद यदि अधिकारी उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो यह सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

लालचंद शर्मा ने कहा कि राजधानी देहरादून के गांधीग्राम, गोविंदगढ़, आर्यनगर और प्रेमनगर से जुड़े क्षेत्रों में सड़कें लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं। शहर के कई प्रमुख मार्ग भी जर्जर हालत में हैं, जिससे आम जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी की सड़कों की यह स्थिति तब है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अधिकारियों को निर्देश देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री के आदेशों का ही प्रभावी अनुपालन नहीं हो रहा है, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? क्या संबंधित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी या जनता इसी तरह परेशान होती रहेगी? कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सड़कें किसी भी शहर की बुनियादी सुविधाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

राजधानी में ही सड़कों की ऐसी स्थिति सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को उजागर करती है। टूटी सड़कों के कारण स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और प्रतिदिन आवागमन करने वाले लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

लालचंद शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि देहरादून की बदहाल सड़कों की तत्काल समीक्षा कराई जाए, गांधीग्राम, गोविंदगढ़, आर्यनगर, प्रेमनगर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए तथा मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि राजधानी की जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि बेहतर सड़कें और बुनियादी सुविधाएं चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को न भुगतना पड़े।

चुनावी मोर्चे पर भाजपा की नई ‘घेराबंदी’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में 2०27 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी संगठनात्मक तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है। लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ पार्टी अब संगठन की चुनावी मशीनरी को व्यवस्थित करने और विधानसभा स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा ने विस्तारक योजना के समन्वय के लिए प्रदेश संयोजकों एवं सह-संयोजकों को जिम्मेदारी सौंपी है। इस कदम को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने और चुनावी रणनीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

भाजपा की रणनीति स्पष्ट है कि चुनावी तैयारी केवल चुनाव घोषित होने के बाद शुरू नहीं होगी। पार्टी पहले से ही संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय करने और विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करने पर जोर दे रही है। विस्तारक योजना इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रदेश स्तर पर समन्वय की जिम्मेदारी तय होने से योजना के संचालन, संगठनात्मक गतिविधियों और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच तालमेल बेहतर बनाने की कोशिश होगी। भाजपा की चुनावी सफलता में बूथ प्रबंधन की अहम भूमिका रही है। पार्टी अब इसी आधार को मजबूत करते हुए विधानसभा स्तर पर संगठन की सक्रियता बढ़ाना चाहती है। विस्तारकों के माध्यम से स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की स्थिति और मतदाताओं के साथ संपर्क की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

प्रदेश संयोजकों और सह-संयोजकों

भैलतिरा पुल से लोहे के एंगल चोरी

चमोली(आरएनएस)। डुंग्री-नैणी मार्ग को जोड़ने वाले भैलतिरा पुल से लोहे के एंगल चोरी हो गए हैं। ग्रामीण एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष ज्योति कैलखुरा ने बताया कि यहां से एंगल चोरी हो गए हैं। यह पुल करीब दो-तीन साल पहले बना था। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। उन्होंने लोनिवि और प्रशासन को इसकी सूचना दी और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पांच दशक बाद भी अधूरी द्वारीखाल-बांघाट सड़क की आस

कोटद्वारा। द्वारीखाल से बांघाट तक मोटर मार्ग की ग्रामीणों की पांच दशक पुरानी मांग अब भी सरकारी फाइलों में अटकती है। सड़क निर्माण को लेकर लोनिवि प्रांतीय खंड लैंसडौन की ओर से शासन को कई बार प्रस्ताव और पत्राचार भेजा जा चुका है लेकिन अंतिम स्वीकृति नहीं मिलने से सड़क निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।

ब्रिटिश शासनकाल में दुगड्डा गढ़वाल की प्रमुख मंडी हुआ करती थी। उस दौर में सड़क सुविधा नहीं होने के कारण गढ़वाल के व्यापारी द्वारीखाल-बांघाट के रास्ते पैदल दुगड्डा पहुंचते थे। सामान ढोने के लिए भेड़,

की जिम्मेदारी इस व्यवस्था में समन्वयकारी भूमिका निभाने की होगी। संगठन की प्राथमिकताओं को संबंधित इकाइयों तक पहुंचाना, गतिविधियों में एकरूपता बनाए रखना और निर्धारित कार्यों की प्रगति पर

◆विस्तारक योजना के लिए प्रदेश संयोजकों और सह-संयोजकों को जिम्मेदारी
◆विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की तैयारी
◆विधानसभा स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी

नजर रखना इस योजना को प्रभावी बनाने के महत्वपूर्ण पहलू होंगे। उत्तराखंड में भाजपा के सामने 2०27 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती है। राज्य की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की परंपरा को देखते हुए पार्टी के लिए यह लक्ष्य आसान नहीं होगा। उसे सरकार के कामकाज के साथ-साथ संगठन की मजबूती और जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता को भी साबित करना होगा।

विस्तारक योजना के लिए जिम्मेदारियां तय करना इसी व्यापक तैयारी का संकेत है। भाजपा चाहती है कि चुनाव के समय संगठन के पास सक्रिय कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क हो और विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। पार्टी के लिए यह भी जरूरी होगा कि संगठनात्मक सक्रियता केवल बैठकों तक सीमित न रहे, बल्कि जनता के बीच नियमित संवाद में दिखाई दे। भाजपा आगामी चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा विकास कार्यों को प्रमुखता देना चाहेगी। लेकिन उत्तराखंड में रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण सुविधाओं जैसे मुद्दे भी राजनीतिक बहस के केंद्र में रहेंगे। इन

केदारनाथ धाम में घटने लगी तीर्थयात्रियों की संख्या

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। श्राद्ध पक्ष संपन्न होने और शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही केदारनाथ की यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या में गिरावट आने लगी है। लगातार बढ़ रही ठंड और केदारघाटी में शाम के समय हो रही बारिश को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। यात्रा के शुरूआती दौर में जहां प्रतिदिन 2० से 25 हजार तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। वहीं अब यात्रा के अंतिम चरण में यह संख्या घटकर करीब एक हजार से डेढ़ हजार तक रह गई है। यात्रा सीजन के दौरान वाहनों से भरी रहने वाली सोनप्रयाग पार्किंग भी करीब 6० फीसदी खाली पड़ी है। यात्रियों की घटती संख्या का असर स्थानीय कारोबारियों के साथ ही छोड़े-खच्चर संचालकों और अस्थायी टेंट व्यवसायियों पर भी पड़ने लगा है। यात्रा सीजन के अंतिम चरण में कई छोड़े-खच्चर संचालक और टेंट व्यवसायी सामान समेटकर घरों की ओर लौटने लगे हैं। व्यवसायी जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब लगातार बढ़ रही ठंड और तीर्थयात्रियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए उन्होंने सामान समेटना शुरू कर दिया है।

पांच दशक बाद भी अधूरी द्वारीखाल-बांघाट सड़क की आस

बकरी और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही ग्रामीण इस पुराने पैदल मार्ग को मोटर मार्ग में बदलने की मांग करते आ रहे हैं। लोनिवि प्रांतीय खंड लैंसडौन ने अधीक्षण अभियंता, 12वें वृत्त लोनिवि पौड़ी को भेजे प्रस्ताव में ग्वीन-बाजागांव-बांघाट मोटर मार्ग के छह किलोमीटर हिस्से के नव निर्माण की योजना भेजी थी। प्रस्ताव के अनुसार पहले चरण में सड़क निर्माण पर 43.5० लाख रुपये और पूरी परियोजना पर 354.3० लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

ग्राम ग्वीन निवासी कल्याण सिंह रावत और उपेंद्र सिंह का कहना है कि लंबे समय

सवालों पर मतदाताओं की प्रतिक्रिया चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है।

ऐसे में विस्तारकों के लिए स्थानीय स्तर पर जनता की अपेक्षाओं और असंतोष को समझना महत्वपूर्ण होगा। संगठन की मजबूती का वास्तविक आकलन इसी बात से होगा कि वह जनता के सवालों को कितनी गंभीरता से सुनता है और उन्हें नेतृत्व तक पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाता है। भाजपा की इस पहल को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के मुकाबले संगठनात्मक बढ़त हासिल करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। चुनाव में केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप पर्याप्त नहीं होते मतदाताओं तक पहुंच, उम्मीदवारों की स्वीकार्यता और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी निर्णायक होती है।

हालांकि, संगठनात्मक नियुक्तियां अपने आप में चुनावी जीत की गारंटी नहीं हैं। भाजपा को स्थानीय गुटबाजी, टिकट की दावेदारी और संभावित असंतोष जैसे सवालों से भी निपटना होगा। इसके साथ ही सरकार के प्रदर्शन को लेकर जनता की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर, विस्तारक योजना के समन्वय के लिए प्रदेश संयोजकों और सह-संयोजकों की जिम्मेदारी तय करके भाजपा ने 2०27 के चुनाव की तैयारी को संगठनात्मक स्तर पर गति देने का संकेत दिया है। अब इस पहल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रदेश स्तर पर बनी रणनीति विधानसभा क्षेत्रों और बूथों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है। हैट्रिक का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा को संगठन की ताकत के साथ जनता का भरोसा भी बनाए रखना होगा।

सू- दोकू क्र.054											
		3					7				
9				6		3		8			
	7		9		5		6				
						1		9			
3		8		7			5				
	1		3		9			7			
		2		8		7					
	8				2		4	3			
			1								
नियम			सू-दोकू क्र.53का हल								
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है। 2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है। 3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।			5	2	4	9	6	7	8	1	3
			3	6	7	4	1	8	2	9	5
			8	1	9	3	2	5	4	6	7
			6	3	5	1	9	4	7	2	8
			7	9	8	5	3	2	6	4	1
			2	4	1	7	8	6	5	3	9
			4	5	3	6	7	9	1	8	2
			9	8	6	2	5	1	3	7	4
			1	7	2	8	4	3	9	5	6

पंजाब में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर की गोली मारकर हत्या !

संवाददाता

अमृतसर। पंजाब के मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। गोलीबारी में झोटा का एक साथी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वारदात के बाद पंजाब की कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, परविंदर झोटा एक फार्मैसी पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने दुकान के मालिक से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की, जिसने कथित तौर पर उसी सुबह दुकान से नशीले पदार्थ खरीदे थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि बहस के दौरान दुकान में मौजूद एक व्यक्ति ने झोटा पर गोलियां चला दीं। गोली लगने से उनकी मौत हो गई, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दुकान का मालिक दुकान बंद कर मौके से फरार हो गया। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।



घटना के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर सवाल उठाए। राजा बडिंग ने आरोप लगाया कि परविंदर झोटा पंजाब में नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनके प्रयासों को पर्याप्त समर्थन नहीं दिया। उन्होंने इस घटना को लेकर सरकार की भूमिका और नशे के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल खड़े किए।

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि परविंदर झोटा अपने कैमरे पर नशे के कारोबार से जुड़े लोगों को दिखा रहे थे, तभी कथित तौर पर चिट्ठा बेचने वाली मेडिकल दुकान के मालिक ने उन पर गोली चला दी।

सिंधी बिरादरी ने सुशील छाबड़ा को किया सम्मानित

संवाददाता

देहरादून। सिंधी बिरादरी की ओर से शाइनिंग स्टार ऑफ उत्तराखंड सम्मान से सम्मानित सुशील छाबड़ा के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया।



श्री मनोकामना सिद्ध झूलेलाल मंदिर में सिंधी बिरादरी की ओर से शाइनिंग स्टार ऑफ उत्तराखंड सम्मान से सम्मानित सुशील छाबड़ा के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बिरादरी के सदस्यों ने उन्हें सम्मानित कर उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। समारोह में सिंधी बिरादरी के अध्यक्ष प्रेम कुमार चंदानी, उपाध्यक्ष इंद्र कुमार गोदवानी, महासचिव कृष्ण कुमार इदनानी, सह-सचिव विजय छाबड़ा, कोषाध्यक्ष राजेश चिचड़ा, बिहारी लाल राजपाल, राजकुमार, वितेन्द्र पाहवा और गिरधारी लाल अरोड़ा उपस्थित रहे। इसके अलावा सिंधी यूथ क्लब के अध्यक्ष गौरव कुकरानी सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। सिंधी लेडीज क्लब की ओर से माया चंदानी, भावना इदनानी सहित अन्य सदस्यों ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।

देहरादून की 40 सड़कों का जिम्मा..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

तो इसे राज्य के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में यह परियोजना केवल राजधानी की 40 सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रदेश में सड़क रख-रखाव के भविष्य के माडल के रूप में भी देखी जा सकती है। हालांकि, देहरादून में सफल प्रयोग का दावा करने से पहले इसके परिणामों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जरूरी होगा। सड़क की मौजूदा स्थिति, मरम्मत के बाद उसकी गुणवत्ता, शिकायतों की संख्या और निर्धारित समय में किए गए सुधार जैसे संकेतकों के आधार पर ही इसकी सफलता तय की जानी चाहिए।

दायित्वों की सौगात, चुनावी जिम्मेदारी...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति और विभिन्न मोर्चों को सक्रिय करने की कवायद को व्यापक चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन चुनावी रणनीति की असली परीक्षा जनता के बीच होगी। संगठनात्मक नियुक्तियां तभी प्रभावी साबित होंगी, जब वह स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करें, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करें और जनता के सवालों का जवाब देने में मददगार बनें। केवल पद और जिम्मेदारियां बांटने से चुनावी जीत सुनिश्चित नहीं होती। धामी सरकार के सामने अब दोहरी कसौटी है। दायित्वों के जरिए संगठनात्मक संतुलन बनाए रखना और चुनावी प्रबंधन को प्रभावी बनाना। दायित्वधारियों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपना भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसकी सफलता का फैसला नियुक्तियों की संख्या नहीं, बल्कि उनके परिणाम करेंगे। सवाल यही है कि क्या यह कवायद 2027 की जीत का मजबूत आधार बनेगी या दायित्वों और पदों की राजनीति पर बहस को और तेज करेगी?

‘लोक संस्कृति दिवस’ के रूप में मनाया गया भव्य रामलीला महोत्सव

हमारे संवाददाता

देहरादून। श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून (पंजी.) द्वारा आयोजित ‘भव्य रामलीला महोत्सव 2026’ का प्रथम दिवस ‘लोक संस्कृति दिवस’ के रूप में मनाया गया। श्री गुरु नानक मैदान, रसकोर्स में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक संगीत और पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहन देने की थीम पर आयोजित समारोह में उत्तरकाशी की प्रथम दिवस, पंचतत्वा बैंड की शानदार प्रस्तुति ने बांधा समा।

माटी से जुड़े युवा कलाकारों के ‘पंचतत्वा बैंड’ ने शानदार संगीतमय प्रस्तुति देकर हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भव्य लेजर एंड साउंड शो ने आयोजन की भव्यता बढ़ाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री खजान दास, विधायक विनोद चमोली एवं प्रसिद्ध लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी उपस्थित रहे। महोत्सव के प्रथम दिवस उत्तराखंड



की माटी से जुड़े उत्तरकाशी के युवा कलाकारों के ‘पंचतत्वा बैंड’ की शानदार संगीतमय प्रस्तुति ने हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं, भव्य लेजर एंड साउंड शो ने आयोजन की भव्यता को और आकर्षक बनाया। श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि वर्ष 1952 से पुरानी टिहरी में चली आ रही ऐतिहासिक रामलीला को टिहरी के जलमग्न होने के बाद देहरादून में पुनर्जीवित कर उसकी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभिनव

थापर ने कहा कि वर्ष 2025 में आयोजित ‘भव्य रामलीला महोत्सव’ को लोगों के अपार स्नेह और आशीर्वाद से विभिन्न माध्यमों के जरिए 82 लाख से अधिक दर्शकों ने देखा, जिसके परिणामस्वरूप यह उत्तराखंड की सबसे अधिक देखी जाने वाली रामलीला बनी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक प्रस्तुतियों और आधुनिक लेजर एंड साउंड शो के अद्भुत संगम के साथ डिजिटल लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इस वर्ष एक करोड़ से अधिक दर्शकों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

वशीकरण का ढोंग कर लोगों से ठगी करने वाले 2 ठग गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। वशीकरण का ढोंग कर लोगों को ठगने वाले दो ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पेन कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद किये। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर को गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुयी की पश्चिमी उ.प्र. के 02 शातिर ठग, जो वशीकरण का ढोंग करके लोगों से ठगी करते हैं, चमन विहार क्षेत्र में किराये पर रह रहे हैं, जिनके द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके फर्जी बैंक खाते खुलवाये गये हैं, जिनका इस्तेमाल वे लोगों से ठगी में कर रहे हैं। प्राप्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक पटेलनगर द्वारा पुलिस टीम के साथ चमन विहार स्थित आशियाना होम्स में औचक छापेमारी की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के

दौरान पुलिस द्वारा मौके से 02 व्यक्तियों सलमान पुत्र रियाजुल निवासी शामली उ.प्र. तथा शाहरूख पुत्र शाहिद निवासी जानसठ मुज्जफरनगर को संदिग्धता के आधार पर हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से पुलिस को उनके तथा अन्य लोगों के नाम के आधार कार्ड, पेन कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेन्स, चैक बुक व अन्य दस्तावेज बरामद हुये।

पूछताछ में पुलिस टीम को जानकारी प्राप्त हुयी कि दोनो विगत डेढ माह से पटेलनगर क्षेत्रान्तर्गत चमन विहार में किराये पर रह रहे हैं तथा मूल रूप से शामली तथा मुज्जफरनगर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा खुद को तांत्रिक बताकर लोगों को वशीकरण करने का झूठा ढोंग करके भोले भाले लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। उनके द्वारा लोगो से ठगी करने के लिये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर खुद को वशीकरण विशेषज्ञ/ज्योतिषाचार्य/शास्त्री/तांत्रिक बताते

हुये गोपनीय तरीके से तांत्रिक उपायों, सिद्ध अनुष्ठानों के माध्यम से लोगों को वशीकरण करने तथा पारिवारिक/अन्य समस्याओं को सुलझाने से सम्बन्धित विज्ञापनों को प्रचारित प्रसारित किया गया था तथा उक्त विज्ञापनों में अपनी पहचान को छुपाते हुये लोगो से सम्पर्क हेतु केवल अपने मोबाइल नम्बर दिये गये थे, जिनके माध्यम से वे लोगो से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं को तंत्र विद्या के माध्यम से हल करने का झांसा देकर उनसे धोखाधड़ी से पैसे प्राप्त करते थे। ठगों द्वारा ठगी के प्रयोजन से अपने तथा 02 अन्य व्यक्तियों दिलनवाज पुत्र समीम तथा मौहम्मद भूरा के नाम से फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बनाये गये थे, जिसमें उनके द्वारा मूल पते के तौर पर अपने किराये के पते को अंकित किया गया था। जिनका उपयोग करके उनके द्वारा दिलनवाज तथा मौहम्मद भूरा के नाम से अलग- अलग बैंकों में फर्जी खाते भी खुलवाये गये थे, जिनका उपयोग वह ठगी की रकम को प्राप्त करने वाले थे।

बीएस नेगी महिला प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय युवा संस्कार कार्यक्रम का आयोजन

संवाददाता

देहरादून। ओएनजीसी कौलागढ स्थित बीएस नेगी महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित दो दिवसीय ‘अभिव्यक्ति-26’ सृजन से शिखर तक के अंतर्गत प्रदर्शनी, टैलेंट हंट तथा युवा संस्कार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति, संस्कार, उद्यमिता और नशामुक्त समाज के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। विशिष्ट अतिथियों के रूप में महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल, विधायक कैंट सविता कपूर, राजीव गांधी साहित्य एवं कला परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमती मधु भट्ट, सुश्री इंद्राणी पांधी उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत



एवं पारंपरिक मांगलिक तिलक से हुआ। मुख्य अतिथि एवं अतिथियों ने संस्थान परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, फैशन, होम डेकोर, हस्तनिर्मित उत्पाद तथा छात्राओं द्वारा तैयार विभिन्न रचनात्मक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मंगलाचरण से हुआ। संस्थान की मानद प्रधानाचार्य श्रीमति नमिता मंगरई ने स्वागत संबोधन में अतिथियों का अभिनंदन किया तथा छात्राओं की प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि

धन सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता, भारतीय मूल्यों और सामाजिक जागरूकता पर जोर देते हुए छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने तथा अपनी प्रतिभा को समाज एवं राष्ट्रहित में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में संस्थान की छात्राओं द्वारा ‘हर अंदाज में एक पहचान’ विषय पर आकर्षक स्टाइल शो तथा पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इसके पश्चात इंटर कालेज टैलेट हंट डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने सोलो एवं ग्रुप डांस में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

अकिता भंडारी हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने रखा मौन उपवास



हमारे संवाददाता देहरादून। अकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीवीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल तथा इस प्रकरण में आरोपों का सामना कर रहे भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाये जाने के विरोध में उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में आज देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क में मौन उपवास एवं सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मौन

उपवास रखकर अकिता भंडारी को न्याय दिलाने तथा हत्याकांड में कथित वीवीआईपी की भूमिका की सीबीआई जांच में तेजी लाये जाने की मांग की। सत्याग्रह से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाये जाने का किया विरोध

गणेश गोदियाल ने कहा कि अकिता भंडारी हत्याकांड केवल एक बेटी की निर्मम हत्या का मामला नहीं, बल्कि उत्तराखण्ड की अस्मिता, मातृशक्ति के सम्मान तथा प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा अत्यन्त संवेदनशील विषय है।

गोदियाल ने कहा कि अकिता भंडारी हत्याकांड में जिस वीवीआईपी की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठाये जाते रहे हैं, उन आरोपों की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी परन्तु इस मामले में सीबीआई जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड में वीवीआईपी की सच्चाई जनता के सामने लाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम जैसे संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल बनाये जाने के निर्णय ने प्रदेश की जनता के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सत्यता का निर्धारण निष्पक्ष जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया से ही होना चाहिए, लेकिन गंभीर आरोपों और सार्वजनिक सवालों का जवाब देना भी सरकार का नैतिक दायित्व है। परन्तु भाजपा सरकार नहीं चाहती कि आने वाली सरकार दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सके इसलिए उन्हें राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बिठा दिया गया है।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन होंगे उत्तराखंड के नए राज्यपाल

कार्यालय संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड को नया राज्यपाल मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डा.ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। वह वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से 12 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की गई।

डा. बिसेन मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। वह मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी चुने गए थे। इसके अलावा वह चार बार विधायक रहे हैं। किसान परिवार से संबंध रखने वाले बिसेन का जन्म 14 मई 1952 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पिपरिया गांव में हुआ था। राजनीति में आने से पहले वह आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डा. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके दीर्घ राजनीतिक अनुभव, जनसेवा के प्रति समर्पण और मार्गदर्शन से प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी।

राष्ट्रपति भवन की अधिसूचना के अनुसार, ओम प्रकाश माथुर को केरलम, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर को तमिलनाडु, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, डा. सुधा यादव को कर्नाटक और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के प्रभावी होने की तिथि संबंधित राज्यपालों के पदभार ग्रहण करने की तारीख होगी।



मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सांसद बिसेन लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का स्थान

दीपावली के सामान से भरे ट्रक के जलने से लारवों का सामान स्वाह

हमारे संवाददाता नैनीताल। नैनीताल के ज्यूलिकोट एन.एच.में दीपावली के सामान से भरे ट्रक में आज सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग व पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया। दिल्ली से नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग 109 में आज तड़के सवेरे पहाड़ों को सामान ले जाते एक ट्रक में अचानक आग लग गई। पटाखों की तरह तेज ध्वनि सुनकर सड़क पर मौजूद लोगों ने पहले इसे पटाखे समझा और दोनों तरफ का ट्रैफिक दूर दूर रुक गया। दमकल विभाग और ज्यूलिकोट पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन तब तक स्थानीय लोगो ने चालक को निकालने में मदद की। स्थानीय लोगों ने बताया कि सामान के जलने में पटाखों सा अहसान हो रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक हल्द्वानी से अल्मोड़ा के द्वाराहाट की तरफ जा रहा था। ट्रक में खाद्य सामग्री के साथ पेंट, वाशिंग मशीन आदि लदा था। ट्रक को चालक दीप सिंह बिष्ट चला रहे थे।



जंतर-मंतर में गेट कूदकर अंदर पहुंचे सौरभ दास और आशुतोष रांका, हिरासत में!

संवाददाता नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सौरभ दास को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक, सौरभ अपने कुछ साथियों के साथ जंतर-मंतर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उनके साथ पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका को भी हिरासत में लिया गया है। इस दौरान तिरंगा लहराया गया और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई।

बताया जा रहा है कि सौरभ दास, आशुतोष रांका और सीजेपी के कुछ अन्य लोग जंतर-मंतर के पास जेडीयू दफ्तर के परिसर की तरफ से अंदर आए। इसके बाद वे गेट से कूदकर जंतर-मंतर के एक हिस्से में पहुंच गए। वहां मौजूद दिल्ली पुलिस ने सभी को तुरंत हिरासत में ले लिया। इस



मामले में पुलिस की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और मुख्य चुनाव

आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर पार्टी नेता आशुतोष रांका की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि आशुतोष रांका जंतर-मंतर पर तिरंगा लहरा रहे हैं। तस्वीर में रांका के हाथ में तिरंगा दिखाई देता है और दिल्ली पुलिस के कई जवान उन्हें पकड़े हुए नजर आते हैं। उनके आसपास पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर के जरिए पार्टी की ओर से प्रदर्शन के दौरान की स्थिति सामने रखी गई।

इस घटनाक्रम में तिरंगा लहराने और सुरक्षा घेरा पार करने के साथ-साथ पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गईं।

स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार

संवाददाता देहरादून। पुलिस ने स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू कालोनी थाना पुलिस ने सपेरा बस्ती पुल के पास एक महिला को संधिस्थ अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रोकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खड़ी हुई। पुलिस ने पीछा कर उसको थोड़ी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 12.78 ग्राम स्मैक बरामद कर ली। पूछताछ में उसने अपना नाम बुलबुल पत्नी रोहित निवासी मोथरोवाला बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

संवाददाता नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई उनकी कथित टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। यह कानूनी विवाद राहुल गांधी द्वारा साल 2018 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि राहुल गांधी ने



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें कथित तौर पर चोरों का सरदार और कमांडर-इन-थीफ कहा था। इन टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई महाराष्ट्र की एक मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही थी।

निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर विचार करने की भी सहमति जताई है, जिसमें राहुल गांधी को साल 2019 में जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी किया है और मानहानि की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का स्पष्ट आदेश पारित किया है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक कांति कुमार

संपादक पुष्पा कांति कुमार समाचार संपादक आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार: वी के अरोड़ा, एडवोकेट बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।

मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।